SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री सभापति: श्री राम विचार नेताम और उसके बाद श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार बोलेंगे, इनका सब्जेक्ट एक ही है, स्टेट्स अलग हैं, लेकिन एक के बाद एक बोलेंगे।

Implementation of the Pradhan Mantri Aawas Yojana-Gramin (PMAY-G) in Chhattisgarh

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी प्रधान मंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किन्तु छत्तीसगढ़ के आवासहीन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एक माननीय सदस्य: सर, यह एलिगेशन है।

श्री राम विचार नेताम: यह एलिगेशन नहीं है, मैं आगे बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: आप सुनिये, यदि कोई आरोप है, तो मैं देखूंगा।

श्री राम विचार नेताम: महोदय, वर्ष 2019-20 में 1,51,100 और 2020-21 में 6, 48,863 आवासों के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति का लक्ष्य मिला था, परन्तु राज्य सरकार ने मात्र 1,20,000 आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार लगभग 8,60,000 आवासहीन परिवार इस मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाएंगे। पीएम आवास योजना में केन्द्र सरकार द्वारा साठ फीसदी राशि और राज्य

सरकार द्वारा चालीस फीसदी राशि के अनुपात से स्वीकृति दी जाती है। विगत दो वर्षों के पीएम आवास योजना की राशि के लगभग एक हज़ार करोड़ राज्य सरकार द्वारा जमा नहीं कराये जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में राज्य शासन अभी तक असमर्थ रहा है। प्रदेश के गरीब व आवासहीन वर्ग, जिनमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग...

श्री सभापति: सुझाव दीजिए।

श्री राम कुमार नेताम: सामान्य वर्ग के अति गरीब लोग हैं। इनके खाते में राशि नहीं आने से वहां की गरीब जनता ऑफिसेज़ के चक्कर लगाते-लगाते परेशान है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय को गम्भीरता से लेते हुए केन्द्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवासों को स्वीकृति देने एवं सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार को पुनः निर्देश जारी करें, धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, in the State of Andhra Pradesh, 27,350 houses were constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin Scheme during 2017-18; and in 2018-19, 18,679 houses were constructed, whereas, in 2019-20 and 2020-21, no house has been constructed despite the release of funds by the Central Government. I came to know that the Central Government has released Rs. 300 crores but the State Government did not release its share and no house has been constructed, and the funds have to be utilized. Earlier the State Government planned to identify the beneficiaries and was also planning to construct 10 lakh houses in the rural areas, but out of which 6.2 lakh houses have been cancelled by the present Government and the beneficiaries have also lost their right to get the houses. Likewise, in the urban areas also, as per the shear wall technology issued by the Ministry of Urban Development, Government of India, 2,62,216 houses have been constructed, almost completed, but, unfortunately, the possession of these houses is not delivered to the beneficiaries till now.

MR. CHAIRMAN: What is your suggestion? Please keep in mind the time.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Therefore, I request the Central Government to take the necessary steps and direct the State Government to deliver possession of the houses immediately and also take steps to construct the houses under Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin Scheme in order to render development and welfare to the poor people in the State of Andhra Pradesh.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: When two people's names are there, the first Member will get two minutes and the second person will get one minute. Keep that in mind. Now, Shrimati Mamata Mohanta.

Need for opening of a Navodaya Vidayalya at Mayurbhanj in Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर माता-पिता की तमन्ना होती है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर खूब बड़ा बने और दुनिया में खूब नाम रोशन करे। इन स्वप्नों को पूरा करने में जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी संदर्भ में, मैं सरकार का ध्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर सबडिवीज़न में एक नवोदय विद्यालय की माँग की ओर आकर्षित कर रही हूँ। मयूरभंज के जनसाधारण कृषि और कृषि श्रम के आधार पर जीवनयापन करते हैं। यह जनजाति बहुल पिछड़ा जिला है और अधिकांश लोग गरीब हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में बहुत रुचि रखते हैं, पर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्राइवेट स्कूल से शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। वह जिला बहुत बड़ा है। वहाँ एक नवोदय विद्यालय है, लेकिन ज्यादा छात्र होने से कई प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।